



## ULB चुनावों में महिला आरक्षण का नगालैंड का वरिध

### प्रलिस के लयः

[शहरी स्थानीय नकलय, महिलाओं के लय आरक्षण](#)

### मेन्स के लयः

संवधान के अनुच्छेद 371A द्वारा नगालैंड को प्राप्त वशष प्रावधान, [भारत में शहरी स्थानीय नकलयों \(ULB\) की संरचना और कार्य](#)

### चरचा में कयों?

शहरी स्थानीय नकलय (ULB) चुनावों में महिलाओं के लय सीटों के आरक्षण को लेकर नगालैंड में हालय वववाद के कारण राज्य में वभिन्न हतधरकों के बीच बहस शुरु हो गई है ।

- यह मुद्दा नगालैंड नगरपालका अधनलय, 2001 पर केंद्रत है जसके तहत [भारतीय संवधान के 74वें संशोधन](#) के अनुसार ULB चुनावों में महिलाओं के लय 33% आरक्षण अनवयर है ।

### 74वाँ संवधान संशोधन अधनलयः

- वर्ष 1992 में पी.वी. नरसमिहा राव की सरकार के दौरान 74वें संशोधन अधनलय के माध्यम से शहरी स्थानीय सरकारों को संवधानक दरजा प्रादान कय गय था । यह 1 जून, 1993 को लागू हुआ ।
  - इसमें भाग IX-A जोड़ा गय है और अनुच्छेद 243-P से लेकर 243-ZG तक प्रावधान शामिल हैं ।
  - इसके अतरकत इस अधनलय के तहत संवधान में 12वीं अनुसूची को भी शामिल कय गय । इसमें नगर पालकाओं के 18 कार्यात्मक वषय शामिल हैं ।

### ULB चुनावों में महिला आरक्षण का नगालैंड के वरिध का कारणः

- महलाओं के लय आरक्षण का वषय परंपरा के खलाफः
  - अधकांश पारंपरक आदवसी और शहरी संगठन महिलाओं के लय सीटों के 33% आरक्षण का वरिध करते हैं, उनका तर्क है कयह संवधान के अनुच्छेद 371A द्वारा नगालैंड को प्रादान कय गए वशष प्रावधानों का उल्लंघन है ।
    - [अनुच्छेद 371A](#) के अनुसार, नगालैंड वधानसभा की सहमती के बना, संसद नगाओं के सामाजक अथवा धार्मक रीत-रवजाओं, कानूनी वववादों को हल करने के उनके प्राथागत कानूनों और प्राक्रयाओं को प्राभावत करने वाले कानूनों को प्रात नही कर सकती है ।
    - नगालैंड के शीर्ष आदवसी नकलय, नगा होहो का तर्क है कय महिलाएँ पारंपरक रूप से नरणय लेने वाली संस्थाओं का हससा नही रही हैं ।
    - नगालैंड एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ ULB की सीटें महिलाओं के लय आरक्षत नही हैं ।
- प्रादर्शनकारयों की मांगः
  - आदवसी नकलयों और नागरक समाज संगठनों ने तब तक चुनावों का बहषकार करने की धमकी दी है जब तक कय नगरपालका अधनलय, 2001 में महिला आरक्षण को ध्यान में रखते हुए "नगा लोगों की मांग की पूरी तरह से समीक्षा और पुनरलेखन नही कय जाता है" ताकयह अनुच्छेद 371A का उल्लंघन न करे ।
- नगालैंड में पछला ULB चुनावः
  - नगालैंड में पहला और एकमात्र नकलय चुनाव 2004 में महिलाओं के लय सीटों के आरक्षण के बना आयोजत कय गय था ।
    - वर्ष 2006 में राज्य सरकार ने महिलाओं के लय 33% आरक्षण को शामिल करने हेतु नगरपालका अधनलय 2001 में संशोधन कय, जसका वयापक वरिध हुआ और परणामस्वरूप वर्ष 2009 में ULB चुनावों को अनशक्त काल के लय स्थगत कर दय गय था ।
      - मार्च 2012 में चुनाव कराने के प्रायासों का भी वयापक वरिध हुआ, साथ हीसतंबर 2012 में राज्य वधानसभा ने

नगालैंड को महिलाओं हेतु आरक्षण से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 243T से छूट देने का प्रस्ताव पारित किया।

- इस प्रस्ताव को वर्ष 2016 में रद्द कर दिया गया था और 33 प्रतिशत आरक्षण के साथ नागरिक निकायों के चुनावों को एक महीने बाद अधिसूचित किया गया जिस कारण फरि से व्यापक अशांति देखी गई।
- सरकार ने फरवरी 2017 में चुनावों को शून्य और नरिस्त घोषित करने की प्रक्रिया की घोषणा की।

## शहरी स्थानीय निकाय (ULB):

### ■ वषिय:

- शहरी स्थानीय निकाय (ULBs) छोटे स्थानीय निकाय हैं जो एक नरिदषिट आबादी वाले शहर या कस्बे को प्रशासति या नरिंतरति करते हैं।
- ULBs के अधिकार क्षेत्र में संबंधित राज्य सरकारों द्वारा सौंपे गए कार्यों की एक लंबी सूची है जिसमें सार्वजनिक स्वास्थ, कल्याण, नयामक कार्य, सार्वजनिक सुरक्षा, सार्वजनिक बुनयादी ढाँचे और वकिस गतविधियाँ आदि शामिल हैं।

### ■ संरचना:

- **शहरी स्थानीय सरकार** में आठ प्रकार के शहरी स्थानीय निकाय शामिल हैं।
  - नगर नगिम:
    - **नगर नगिम** आमतौर पर **बड़े शहरों** जैसे- बंगलूरु, दलिली, मुंबई, कोलकाता आदि में हैं।
  - नगर पालकि:
    - छोटे शहरों में **नगर पालकिओं** का प्रावधान है।
    - नगर पालकिओं को अकसर अन्य नामों से भी जाना जाता है जैसे- **नगर पालकि परिषद, नगर पालकि समति, नगर पालकि बोर्ड** आदि।
  - अधिसूचित क्षेत्र समति:
    - तेज़ी से वकिसति हो रहे कस्बों और **मूलभूत सुवधियों से वंचित कस्बों** के लयि अधिसूचित क्षेत्र समतियों का गठन कयिा जाता है।
    - अधिसूचित क्षेत्र समति के सभी सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा मनोनीत कयिा जाता है।
  - नगर क्षेत्र समति:
    - नगर क्षेत्र समति की व्यवस्था **छोटे शहरों** में पाई जाती है।
    - इसे **स्ट्रीट लाइटिंग, ड्रेनेज रोड और कंज़र्वेंसी** की व्यवस्था आदि सुनशित करने का अधिकार प्राप्त है।
  - छावनी बोर्ड:
    - यह आमतौर पर छावनी क्षेत्र में रहने वाली नागरिक आबादी के प्रशासन के लयि स्थापति कयिा जाता है।
    - इसे **केंद्र सरकार** द्वारा स्थापति और नरिंतरति कयिा जाता है।
  - टाउनशिप:
    - टाउनशिप संयंतर के आस-पास स्थापति कॉलोनियों में रहने वाले कर्मचारियों और शर्मकों को बुनयादी सुवधियाँ प्रदान करने के लयि शहरी सरकार का दूसरा रूप है।
    - इसका कोई नरिवाचति सदस्य नहीं है और यह केवल नौकरशाही संरचना का वसितार है।
  - पोर्ट ट्रस्ट:
    - पोर्ट ट्रस्ट **मुंबई, चेन्नई, कोलकाता** आदि बंदरगाह क्षेत्रों में स्थापति कयिा जाते हैं।
    - यह पोर्ट (बंदरगाह) का प्रबंधन और देखभाल करता है।
    - यह उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को बुनयादी नागरिक सुवधियाँ भी प्रदान करता है।
  - वशिष प्रयोजन एजेंसी:
    - ये एजेंसियाँ नगर नगिमों या नगरपालकिओं से संबंधित नरिदषिट गतविधियों या वशिषित कार्यों को पूरा करती हैं।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, पछिले वर्ष के प्रश्न

**[?/?/?/?/?]:**

प्रश्न. पेट्रोलयिम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के हाल के नरिदेशों को 'नगाओं' द्वारा उनके राज्य को मली वशिषित स्थिति को रद्द करने के खतरे के रूप में देखा गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371A के आलोक में इसकी वविचना कीजयिे। (2013)

**स्रोत: द हद्वि**

